



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]
No. 19]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 1985/साघ 2, 1906
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 1985/MAGHA 2, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

श्रम मंत्रालय

मंकल्प

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1985

फा. सं. यू. 11013/1/84—आर डब्ल्यू.—पिछले कुछ समय से श्रम मंत्रालय में विचार किया जा रहा है कि देश में मजदूरों के कार्य की दशाओं में सुधार लाने के लिए कौन से संवैधानिक और प्रशासनिक उपाय किए जाने चाहिए। काफी सोच-विचार के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय किया है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों, कामगारों के प्रतिनिधियों और नियोजकों के प्रतिनिधियों आदि का एक त्रिपक्षीय अध्ययन दल गठित किया जाए। त्रिपक्षीय अध्ययन दल का गठन और विचारार्थ विषय निम्ना-नुसार होंगे :—

2. गठन

केन्द्रीय सरकार

1. अपर सचिव
श्रम मंत्रालय
नई दिल्ली।

अध्यक्ष

2. महानिदेशक (श्रम और कल्याण) सदस्य सचिव और संयुक्त सचिव श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधि, सदस्य नई दिल्ली।
4. वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि, सदस्य नई दिल्ली।
5. योजना आयोग का प्रतिनिधि, सदस्य नई दिल्ली।
6. जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय सदस्य का प्रतिनिधि, नई दिल्ली।
7. केन्द्रीय समुद्रीय मत्स्य पालन अनु-संघान संस्थान का प्रतिनिधि, (कोचीन) सदस्य
8. महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रति-सदस्य निधि

9. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का सदस्य
प्रतिनिधि
10. केरल राज्य सरकार का प्रति- सदस्य
निधि
11. पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार का सदस्य
प्रतिनिधि
केन्द्रीय नियोक्ताओं के संगठन :
12 से 15
केन्द्रीय नियोक्ताओं के संगठन
द्वारा नामित किए जाने वाले
नियोक्ताओं के प्रतिनिधि— 4 सदस्य
केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन
16. यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस सदस्य
(एल. एस.)
17. सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन सदस्य
18. ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन कमेटी सदस्य
19. भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सदस्य
कांग्रेस

3. त्रिपक्षीय अध्ययन दल के विचारार्थ विषय निम्ना-
नुसार होंगे :—

(क) मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की नावों तथा मछुआरों के विभिन्न वर्गों, कार्य-प्रचालन के स्वरूप उनकी कार्य-प्रणाली और रहन-सहन की दशाओं—जैसे कार्य करने का समय, दुर्घटनाएं जिनका वे शिकार होते हैं, ऐसी दुर्घटनाओं के लिए बीमे की वर्तमान व्यवस्थाएं मछली पकड़ने में उपयोग में लाए जाने वाले उपस्कर, बेय मजदूरी/पारिश्रमिक, भ्रष्टाचार पेय जल, चिकित्सा सहायता, बच्चों को छात्रवृत्ति आदि के अंतर्गत मछुआरों को उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं का पता लगाना और ये सुविधाएं उन्हें कितनी प्राप्त हो रही हैं ;

(ख) उन मौजूदा वैधानिक प्रावधानों, जो कि मछुआरों (मजदूरी पर लगे और स्वयं रोजगार प्राप्त दोनों) को लागू होते हैं और वैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन में समय-समय पर उठने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना ; और

(ग) उत्पादकों तथा निर्यातकों पर आवश्यकता के अनुसार कर लगाकर कल्याण निधि के गठन के साथ-साथ वैधानिक और प्राशासनिक उपायों पर विचार करना और उनके ब्योरे तैयार करना जिससे कि मछुआरों के कार्य और रहन-सहन की दशाओं में सुधार लाया जा सके।

4. इस में तीन अतिरिक्त व्यक्ति सहयोगी किए जा सकते हैं जो अपने विशिष्ट ज्ञान से दल की सहायता करेंगे।

5. दल अपने गठन की तारीख के एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आदेश

इस संकल्प की प्रतिलिपियां निम्नलिखित को भेजी जाएं:-

1. संबंधित सदस्य

2. श्रम सचिव सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत के प्रसाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

ए. के. श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव/महानिदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR RESOLUTION

New Delhi, the 22nd January, 1985

File No. U-11013|1|84-RW.—For sometime past the Ministry of Labour has been considering as to what legislative and administrative measures should be taken for improving the working and living conditions of the Fishermen in the country. After due consideration it has been decided by the Government to constitute a Tripartite Study Group consisting of the officials of the Central & State Governments, Workers' representatives and the Employer's representatives etc. The composition of the Tripartite Study Group and the terms of reference will be as under :—

2. Composition :

Central Government

CHAIRMAN

(1) Additional Secretary Ministry of Labour,
New Delhi.

Member-Secretary

(2) DG(LW) and Joint Secretary, Ministry of Labour, New Delhi.

MEMBERS

(3) Representative of the Ministry of Agriculture,
New Delhi.

(4) Representative of the Ministry of Commerce,
New Delhi.

(5) Representative of the Planning Commission,
New Delhi.

(6) Representative of the Ministry of Shipping &
Transport, New Delhi.

(7) Representative of the Central Marine Fisher-
ies Research Institute (Cochin).

- (8) Representative of the Govt. of Maharashtra.
- (9) Representative of the Govt. of Uttar Pradesh.
- (10) Representation of the Govt. of Kerala.
- (11) Representative of the Govt. of West Bengal.

Central Employer's Organisation

(12) to (15)

Representatives of the employers to be nominated by the Central Employers' Organisation.

—4 Members

Central Trade Union Organisations :

MEMBERS

- (16) United Trade Union Congress (LS)
- (17) Centre of Indian Trade Unions
- (18) Trade Union Co-ordination Committee.
- (19) Indian National Trade Union Congress.

3. The terms of reference of the Tripartite Study Group will be as under :—

- (a) To identify the different types of fishing boats as well as different categories of fishermen, nature of operations, their working and living conditions, such as hours of work, accidents to which they are vulnerable, existing provisions for insurance against such accidents, fishing equipments used, wages/remunerations payable, existing facilities available to the fishermen under housing, drinking water, medical aid, scholarships to children etc. and

the extent to which they are availing themselves of these benefits ;

- (b) To study existing legislative provisions which are applicable to the fishermen (both wage employed and self-employed) and the difficulties which may have arisen from time to time in the implementation of the statutory provisions; and
- (c) To consider and formulate the details of legislative and administrative measures including constitution of a Welfare Fund, by levy of cess on the manufacturers/export houses as may be considered necessary, for improving the working and living conditions of the Fishermen.

4. The Group may coopt upto three persons who by virtue of their special knowledge will be asked to assist the Group.

5. The Group will submit its report within a period of one year from the date of its constitution.

ORDER

Copies of the Resolution may be sent to :—

- (i) Members concerned.
- (ii) Labour Secretaries, All State/Union Territories Governments.

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary.

A. K. SRIVASTAVA,

Jt. Secy. | Director General (Labour Welfare)

